तीसरी तिमाही में 8.1% रह सकती है देश की वृद्धि दर

■ मजबूत घरेलू मांग के चलते बनी रहेगी शानदार तेजी

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और अमेरिकी व्यापार नीतियों में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था अपने मजबूत घरेलू आधार के दम पर मजबूती से खड़ी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष (FY26) की तीसरी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 8.1 प्रतिशत के करीब रहने का अनुमान है। वहीं, दूसरी ओर मूडीज एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट यह संकेत देती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित 15 प्रतिशत के एकमुश्त टैरिफ से ग्लोबल ट्रेड और विशेष रूप से एशिया-प्रशांत क्षेत्र के व्यापारिक समीकरणों में बड़े बदलाव आ सकते हैं। एसबीआई की रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि भारत की आर्थिक वृद्धि का मुख्य इंजन उसकी घरेलू मांग है।

खपत में वृद्धिः कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों से मिल रहे सकारात्मक संकेतों के कारण ग्रामीण खपत मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही, पिछले त्योहारी सीजन के खर्च और राजकोषीय प्रोत्साहन से शहरी खपत में भी निरंतर सुधार देखने को मिला है। जीडीपी अनुमानः पहली अग्रिम रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 (FY26) के लिए भारत की कुल जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

बेस ईयर में बदलावः भारत अपने जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर रहा है, जिसके नए आंकड़े 27 फरवरी 2026 को जारी होंगे। यह नया बेस ईयर डिजिटल कॉमर्स और सर्विस सेक्टर के बढ़ते प्रभाव को बेहतर ढंग से दर्शाएगा।

महंगाई दर का लक्ष्यः उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का बेस ईयर भी 2024 कर दिया गया है। आरबीआई (RBI) गवर्नर संजय मल्होत्रा के अनुसार, इसके आधार पर अप्रैल की मौद्रिक नीति में महंगाई दर के लक्ष्यों के संशोधित ढांचे की समीक्षा की जाएगी।

अमेरिकी टैरिफ नीति और वैश्विक व्यापार पर असरः मूडीज जहां भारत का घरेलू बाजार मजबूत है, वहीं विदेशी मोर्चे पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने ट्रंप प्रशासन के 'कंट्री-स्पेसिफिक' (देश-विशिष्ट) टैरिफ ढांचे को खारिज कर दिया है। इसके जवाब में ट्रंप ने 150 दिनों के लिए सभी आयातों पर 10 प्रतिशत का अस्थायी टैरिफ लगाया है और इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की योजना है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र को राहत मूडीज के मुताबिक, इस 15% एकसमान टैरिफ से चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के उन देशों को फायदा हो सकता है, जो अब तक भारी टैरिफ का सामना कर रहे थे।

हालांकि, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान पर इसका सीमित असर होगा क्योंकि उनके बेस टैरिफ पहले से ही 15% के करीब हैं। भारत की व्यापारिक वार्ताओं पर अनिश्चितताः सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने भारत और इंडोनेशिया के साथ अमेरिका की व्यापारिक वार्ताओं पर अनिश्चितता के बादल ला दिए हैं। भारत ने वाशिंगटन भेजे जाने वाले अपने प्रतिनिधिमंडल का दौरा भी फिलहाल टाल दिया है। अब आगे क्या? आने वाले समय में वैश्विक व्यापार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मूडीज ने चेतावनी दी है कि टैरिफ की दीवारें ऊंची होने की आशंका से अमेरिकी आयातक जल्दबाजी में अपने शिपमेंट मंगाने का प्रयास कर सकते हैं।

इसके अलावा, कंपनियों द्वारा पहले चुकाए गए टैरिफ की वसूली की कोशिशें कानूनी विवादों को जन्म दे सकती हैं। हालांकि अमेरिका नए कानूनी रास्तों से टैरिफ बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन भारत की 8.1 प्रतिशत की अनुमानित तिमाही ग्रोथ यह आश्वस्त करती है कि मजबूत घरेलू खपत के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों को सहने में पूरी तरह सक्षम है।

खबर एक्सप्रेस

अब माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री की मदद से काम होगा और भी आसान

नई दिल्ली। फोनपे ने आज एक नया एआई -पावर्ड 'नेचुरल लैंग्वेज सर्च' फीचर लॉन्च किया है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री की मदद से बनाया गया है। फोनपे के को-फाउंडर, होल-टाइम डायरेक्टर और सीटीओ , राहुल चारी ने कहा, इस फीचर की खासियत यह है कि अब फोनपे इस्तेमाल करने वाले लोग इन-ऐप टास्क को टेक्स्ट या वॉयस कमांड देकर कर सकेंगे। इससे ऐप को इस्तेमाल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा और हर यूजर को अपनी जरूरत के हिसाब से बेहतर अनुभव मिलेगा।यह फीचर माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे अब आपको ऐप के अंदर अलग-अलग बटन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सीधे आपकी बात को समझकर आपको सही जगह पर पहुँचा देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं "हेमंत को 20 रुपये भेजो", तो ऐप अपने आप पेमेंट वाला पेज खोल देगा और हेमंत का नाम चुन लेगा। इसी तरह, "फास्टैग रिचार्ज" या "गोल्ड का भाव" जैसे कमांड देने पर ऐप आपको सीधे उस पेज पर ले जाएगा जहाँ आपको आपकी जरूरत की जानकारी या ट्रांजैक्शनल का ऑप्शन मिल सके।यह फीचर सिर्फ पैसे भेजने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी जरूरत को भी समझ लेता है। यह आसानी से पहचान सकता है कि आप पेमेंट करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं या फिर मदद के लिए कस्टमर सपोर्ट से बात करना चाहते हैं।

एआई इम्पैक्ट पर 'नई दिल्ली घोषणापत्र' में शामिल हुए 91 देश और वैश्विक संगठन

नई दिल्ली। एआई इम्पैक्ट पर 'नई दिल्ली घोषणापत्र' में शामिल होने वाले देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह जानकारी मंगलवार को दी गई। पिछले सप्ताह नई दिल्ली में आयोजित 'एआई इम्पैक्ट समिट 2026' का समापन नई दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ हुआ। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि 21 फरवरी 2026 तक 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने इस घोषणा का समर्थन किया था। इसके बाद बांग्लादेश, कोस्टा रिका और याटोमाला भी इससे जुड़ गए, जिससे हस्ताक्षरकताओं की कुल संख्या 91 हो गई है। यह घोषणा एआई का उपयोग आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए करने पर व्यापक वैश्विक सहमति को दर्शाती है। 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के सिद्धांत से प्रेरित यह घोषणा इस बात पर जोर देती है कि एआई के लाभ पूरी मानवता तक समान रूप से पहुंचने चाहिए। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, घोषणा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बहु-हितधारक भागीदारी को मजबूत करने, राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करने और सुलभ तथा भरोसेमंद ढांचे के माध्यम से एआई को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। घोषणा में आर्थिक परिवर्तन में एआई की भूमिका, ओपन-सोर्स और सुलभ एआई इकोसिस्टम का महत्व, ऊर्जा-कुशल एआई अवसंरचना की आवश्यकता, विज्ञान, शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में एआई की भूमिका बढ़ाने तथा वैश्विक सहयोग को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। बयान में कहा गया है कि मजबूत डिजिटल अवसंरचना और सस्ती व सार्थक कनेक्टिविटी एआई को लागू करने और उसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए आवश्यक है। 'वसुधैव कुटुंबकम' के सिद्धांत से प्रेरित होकर इसमें एआई संसाधनों की वहनीयता और पहुंच बढ़ाने के महत्व को स्वीकार किया गया है, ताकि सभी देश अपने नागरिकों के लाभ के लिए एआई का विकास, अपनाना और उपयोग कर सकें। घोषणा में यह भी कहा गया है कि सुरक्षित, भरोसेमंद और मजबूत एआई को आगे बढ़ाना समाज और अर्थव्यवस्था के अधिकतम लाभ के लिए विश्वास निर्माण की बुनियाद है।

केंद्र ने कच्चे जूट के लिए एमएसपी बढ़ाई, प्रति क्विंटल 275 रुपए का इजाफा किया

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कच्चे जूट के लिए एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया। इससे जूट से जुड़े किसानों को अपनी फसल पर पहले के मुकाबले अधिक मुनाफा कमाने में मदद मिलेगी। विपणन सत्र 2026-27 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित आर्थिक कार्य मंत्रिमंडलीय समिति में दी गई। आधिकारिक बयान में कहा गया कि 2026-27 सीजन के लिए कच्चे जूट (टीडी-3 ग्रेड) का एमएसपी 5,925 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इससे जूट के अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर 61.8 प्रतिशत का लाभ सुनिश्चित होगा। विपणन सीजन 2026-27 के लिए कच्चे जूट का यह घोषित एमएसपी बजट 2018-19 में सरकार के घोषित अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना एमएसपी निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुरूप है। बयान में आगे कहा गया कि विपणन सत्र 2026-27 के लिए कच्चे जूट का एमएसपी पिछले विपणन सत्र 2025-26 की तुलना में 275 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। सरकार ने कच्चे जूट का एमएसपी 2014-15 में 2,400 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2026-27 में 5,925 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जो कि 3,525 रुपए प्रति क्विंटल (2.5 गुना) की वृद्धि दशार्ता है। वर्ष 2014-15 से 2025-26 की अवधि के दौरान जूट उत्पादक किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि 1342 करोड़ रुपए थी, जबकि वर्ष 2004-05 से 2013-14 की अवधि के दौरान भुगतान की गई राशि 441 करोड़ रुपए थी। सरकार ने बताया कि भारतीय जूट निगम (जेसीआई) मूल्य समर्थन संचालन करने के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना जारी रखेगी और ऐसे संचालन में होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई पूरी तरह से केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी। भारत विश्व का सबसे बड़ा कच्चा जूट उत्पादक देश है, जिसका 99 प्रतिशत से अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में केंद्रित है।

कैबिनेट ने श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1,677 करोड़ रुपए में सिविल एन्क्लेव के विकास को दी मंजूरी

नई दिल्ली। कश्मीर घाटी में विमानन बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा कदम उठाया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1,677 करोड़ रुपए की लागत से सिविल एन्क्लेव के विकास को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने इस परियोजना को स्वीकृति दी है। परियोजना के दायरे में सुरक्षा कर्मियों के लिए बैरकों (आवास) का निर्माण भी शामिल है। करीब 73.18 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला नया सिविल एन्क्लेव एक अत्याधुनिक टर्मिनल भवन से लैस होगा, जिसका कुल क्षेत्रफल 71,500 वर्ग मीटर होगा, जिसमें 20,659 वर्ग मीटर मौजूदा ढांचा शामिल है। यह टर्मिनल पीक समय में 2,900 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा और इसकी वार्षिक क्षमता 1 करोड़ यात्रियों (10 मिलियन प्रति वर्ष) की होगी। कैबिनेट की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "विस्तारित एप्रन क्षेत्र में 15 विमानों के पार्किंग वे होंगे, जिनमें 1 वाइडबॉडी (कोड ई) विमान के लिए स्थान शामिल है (9 मौजूदा और 6 नए प्रस्तावित), जबकि 3,658 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे भारतीय वायुसेना (आईएएफ) द्वारा संचालित होता रहेगा। परियोजना के तहत 1,000 कारों की क्षमता वाला बहु-स्तरीय पार्किंग परिसर भी बनाया जाएगा।

भारतीय शेयर बाजार धड़ाम

सेंसेक्स 1068.74, एनएसई निफ्टी 288.35 अंक टूटा

■ सोमवार को हरे निशान पर बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। भारतीय बाजार मंगलवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी में एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1068.74 अंक या 1.28 प्रतिशत गिरकर 82,225.92 पर बंद हुआ। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 288.35 अंक या 1.12 प्रतिशत गिरकर 25,424.65 पर बंद हुआ।छह लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव व्यापक रहा, जिसमें मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक में करीब 1 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। तेज गिरावट के बीच निवेशकों की संपत्ति में भारी कमी आई। इससे निवेशकों को एक ही दिन में छह लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। तकनीकी शेयरों में कमजोरी का रुझान जारी जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि एआई के संभावित प्रभाव के कारण तकनीकी शेयरों में कमजोरी का रुझान जारी है। भारतीय आईटी कंपनियों के एडीआर में कमजोरी यह संकेत देती है कि यह सेगमेंट दबाव में बना रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का आज बाद में होने वाला स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन और उसमें दिया जाने वाला संदेश वैश्विक बाजारों द्वारा उत्सुकता से देखा जाएगा। इन कारणों से दिखी गिरावट वैश्विक व्यापार और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर अनिश्चितता के बीच निवेशकों का मनोबल कमजोर बना रहा। यह कमजोरी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 10-15 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ ढांचे की घोषणा के बाद टैरिफ संबंधी चिंताओं के फिर से उभरने से उत्पन्न हुई है, जिससे वैश्विक आर्थिक विकास और कंपनियों की आय पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं।

निष्क्रिय पीएफ खातों में पड़ी राशि लौटाई जाएगी

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के 7.11 लाख निष्क्रिय खातों में फंसे 30.52 करोड़ रुपये जल्द संबंधित खाताधारकों या उनके कानूनी वारिसों को लौटाए जाएंगे। श्रम मंत्रालय का यह फैसला ऐसे 31.86 लाख खातों को बंद करने की पहल का हिस्सा है, जो मौजूदा समय में निष्क्रिय पड़े हैं। मंत्रालय के मुताबिक इनमें कुछ खाते 20 साल तक पुराने हैं, जिनमें तीन साल से कोई लेनदेन नहीं हुआ।मंत्रालय ने बताया कि निष्क्रिय खातों को बंद करने के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी ऐसे सात लाख खातों को चुना गया है, जिनमें शून्य से 1,000 रुपये तक राशि जमा है और ये आधार से जुड़े हैं। लिहाजा, ईपीएफओ सीधे उनके खाते में यह पैसे ट्रांसफर कर देगा। इन खातों में 30.52 करोड़ रुपये जमा हैं। पायलट प्रोजेक्ट सफल होने पर बाकी खातों में भी इसी तरह से पैसे लौटा दिए जाएंगे। निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भविष्य निधि एक अनिवार्य सरकारी योजना है। इसमें प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन का 12 फीसदी हिस्सा डालता है, जबकि नियोक्ता की ओर से भी उतना ही योगदान दिया जाता है। लेकिन, जब खाते में तीन साल तक कोई लेनदेन नहीं होता तो यह निष्क्रिय खाते में तब्दील हो जाता है। श्रम मंत्रालय अब ऐसे खातों को अब बंद करने की ओर बढ़ रहा है। कुल 10,903 करोड़ जमा ईपीएफओ में करीब 31.86 लाख निष्क्रिय पीएफ खाते हैं, जिनमें कुल 10,903 करोड़ रुपये जमा हैं। सरकार के मुताबिक ईपीएफओ सदस्य अपना पैसा निकालने के लिए अब आसानी से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन, यह भी देखने में आया है कि जिन खातों में पैसे कम हैं, वहां सदस्य आने-जाने के झंझट से बचने के लिए उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। छोटी राशि बड़ी परेशानी पीएफ की छोटी-छोटी धनराशि बड़ी परेशानी का सबब है, क्योंकि इस तरह से हजारों करोड़ रुपये निष्क्रिय खातों में पड़े हैं।

पीएम सूर्य योजना लाखों परिवारों के लिए बनी वरदान

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश में 30 लाख घरों में रूफटॉप सोलर लगाने की उपलब्धि को भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा का बड़ा मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम है।

प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों को बधाई दी और इसे बचत, स्थिरता और आत्मनिर्भरता से जुड़ा जनआंदोलन बताया।प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रूफटॉप सोलर अपनाने वाले परिवारों ने न केवल अपने बिजली बिल में कमी लाई है, बल्कि देश को हरित ऊर्जा की ओर आगे बढ़ाया है।

उन्होंने कहा कि यह योजना ऊर्जा सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और भविष्य के लिए तैयार भारत बनाने की सरकार की सोच का हिस्सा है।30 लाख घरों तक पहुंची योजना केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब तक 30 लाख घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं।

उन्होंने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। जोशी ने कहा कि यह कदम सूरज की रोशनी को बचत और सतत विकास में बदलने का उदाहरण है। इससे बिजली बिल कम हो रहे हैं और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो रही है। बचत और आत्मनिर्भरता पर जोर सरकार का दावा है कि रूफटॉप सोलर से आम परिवारों को सीधा फायदा मिल रहा है।

बिजली खर्च में कमी के साथ अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचने का भी विकल्प मिलता है।

इससे परिवारों की आय में भी बढ़ोतरी हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रही है।

हरित परिवर्तन की रफ्तार प्रह्लाद जोशी ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रहे हरित परिवर्तन की गति को दशार्ती है। सरकार का लक्ष्य देश को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता घटाकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि आने वाले समय में और अधिक घरों को इस योजना से जोड़ा जाएगा।

सरकार का लक्ष्य है कि हर परिवार तक सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा पहुंचे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसी गति से रूफटॉप सोलर का विस्तार होता रहा तो भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।

चांदी में तेजी जारी, सोना टूटा

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। सोने-चांदी की कीमतों में उथल-पुथल जारी है। चांदी 1140 रुपये की बढ़त के साथ 2.67 लाख प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं सोने का भाव 500 रुपये गिरकर 1.61 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एमसीक्स पर सोने-चांदी का भाव मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे आम उपभोक्ताओं के लिए गहने खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। अप्रैल डिलीवरी के लिए पीले धातु (सोने) की कीमत में 496 रुपये या 0.31 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 7,587 लॉट के कारोबार में 1,61,102 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी करीब Rs.2,65,350 प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही है। कीमतों में आई इस तूफानी तेजी ने निवेशकों और खरीदारों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। खासकर शादी के सीजन और निवेश के लिहाज से सोने-चांदी की मांग पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती खरीदारी, सुरक्षित निवेश की मांग और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण कीमती धातुओं में तेजी का रुख बना हुआ है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया है कि सरकार और केंद्रीय बैंक सोने-चांदी की कीमतों और बढ़ते आयात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती खरीदारी और वैश्विक कारकों के चलते कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी की कीमत हालांकि वैश्विक बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। मजबूत अमेरिकी डॉलर, टैरिफ को लेकर अनिश्चितता और अमेरिका-ईरान तनाव के दबाव में कॉमेक्स गोल्ड अपने तीन सप्ताह के उच्च स्तर से नीचे फिसल गया। स्पॉट गोल्ड करीब 1.5% गिरकर 5,150.38 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जबकि अप्रैल डिलीवरी के लिए अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 1.1% गिरकर 5,170.70 डॉलर प्रति औंस पर रहा। वहीं चांदी में भी तेज गिरावट देखने को मिली और स्पॉट सिल्वर 3.1% टूटकर 85.50 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि इससे एक दिन पहले यह दो सप्ताह के उच्च स्तर पर था।

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN: L65910KL1992PLC009823,
Registered Office : W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.03.2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुनः सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (ऊपर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :

भिवानी, दीनोद गेट भिवानी, 138570730008015,

ऊपर बताई गई नीलामी में हिस्सा लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नीचे दी गई बातों का पालन करना होगा: इच्छुक बोली लगाने वालों को नीलामी के दिन ही एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए 10,000/- रुपये ईएमडी (जो बोली हारने वालों को वापस कर दिया जाएगा) जमा करना होगा। बोली लगाने वालों के पास वैध आईडी कार्ड/पैन कार्ड होना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया 9072607147 पर संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी
मणपुरम फायनेंस लि. हेतु.

बदल रहा लोगों का खरीदारी करने का तरीका

■ ई-कॉमर्स बाजार चार वर्षों में बढ़कर 280-300 अरब डॉलर पहुंचने की संभावना

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। घरेलू ई-कॉमर्स बाजार का आकार 2030 तक करीब 300 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। बोस्टान कंस्ल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

ई-कॉमर्स के चलन के बावजूद ऑफलाइन मार्केट है मजबूत रिपोर्ट में कहा गया है कि ई-कॉमर्स की तेज वृद्धि के बावजूद ऑफलाइन रिटेल मार्केट मजबूत बना हुआ है। यह पिछले चार वर्षों में 13-14 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है।

बाजार ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल के बीच सह-अस्तित्व के चरण में प्रवेश कर रहा है। इसमें मल्टी-चैनल खरीदारी करने वालों के लिए एक सामान्य बात बन गई है। 10 में से पांच ऑफलाइन खरीदार खरीदारी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन चैनलों का उपयोग करते हैं। भारत में कितने लोग ऑनलाइन करते हैं खरीदारी? रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत में वर्तमान में लगभग 30 करोड़ ऑनलाइन खरीदार हैं, जिनके 2030 तक 44 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जिनमें से लगभग 30 प्रतिशत ऑनलाइन खरीदार ग्रामीण भारत से हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ई-कॉमर्स में ई-रिटेल और ई-सेवाएं शामिल हैं। इनका अनुमानित मूल्य क्रमशः 75-85 अरब डॉलर और 45-55 अरब डॉलर है। ई-सेवाओं की वृद्धि दर 20-22 प्रतिशत रहेगी, जबकि ई-रिटेल की वृद्धि दर 16-18 प्रतिशत रहेगी। उपभोक्ताओं की खरीदारी का पैटर्न बदला विभिन्न क्षेत्रों के 12,000 से अधिक उपभोक्ताओं के सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट में कहा गया है कि आजकल खरीदार सुविधा, विश्वास और आवश्यकता के आधार पर स्क्रीन और स्टोर के बीच सहजता से आवागमन करते हैं, ऑनलाइन खोज करते हैं, ऑफलाइन खरीदारी करते हैं और ऑफलाइन खरीदारी करते हैं। महिलाएं ऑनलाइन खरीदारी को अधिक सुरक्षित मानती हैं लगभग दो-तिहाई महिला खरीदारों का कहना है कि वे ऑनलाइन खरीदारी को अधिक सुरक्षित मानती हैं। इसका कारण गोपनीयता, सुगम पहुंच और किसी भी समय स्वतंत्र रूप से खरीदारी करने की क्षमता है। खरीदार हुए अधिक विविधतापूर्ण बीसीजी की पार्टनर और डायरेक्टर कनिका सांघी ने कहा कि भारत के खरीदार अधिक विविधतापूर्ण होते जा रहे हैं। उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं और परिपक्वता के अनुसार विभिन्न प्रारूपों का उपयोग कर रहे हैं। ऑनलाइन खरीदारों का जनसांख्यिकीय मिश्रण अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। इसलिए प्लेटफॉर्म और ब्रांडों को सभी टचपॉइंट्स पर सरल, सुरक्षित और अधिक सहज अनुभव प्रदान करने होंगे। ऑनलाइन ब्रांडों के वार्षिक राजस्व का लक्ष्य क्विक कॉमर्स में 100 प्रतिशत से अधिक की सीएजीआर वृद्धि हुई है, जिससे तत्काल और टॉप-अप खरीदारी मुख्यधारा बन गई है और खरीदारी की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, जबकि सोशल और चैट कॉमर्स में 40-45 प्रतिशत की सीएजीआर वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि ऑनलाइन ब्रांडों को 100 करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व तक पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 11 साल से घटकर लगभग 7 साल हो गया है।